

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत- राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर मुकाम सवाई माधोपुर

संतोष बाई बनाम क्षेत्रिय वन अधिकारी

किस्म मुकदमा 223 आर टी एक्ट.....अपील संख्या 35/21

GCMS NO 2021/59

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
20.3.25	<p>उभयपक्ष अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस अपील पर सुनी गई। अपीलांत ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आराजी ख0न0 62/1505 रकबा 3 बीघा वारानी वाके ग्राम चैनपुर तहसील मासलपुर में वादिया की खातेदारी में दर्ज है जिसका नक्शा उप जिला कलेक्टर करौली के निर्णय दिनांक 30.5.2000 के मुताबिक मौके पर तरमीम हुआ है। इस प्रकार रेस्पो0के खिलाफ दावा पूर्व में डिक्री हो चुका है। नियमानुसार तरमीम दिनांक 28.11.15 तक बदस्तुर सही रही है। उक्त तरमीम को वन विभाग द्वारा मनमाने तरीके से नक्शे के अंदर बीच में नये सिरे से लाल स्याही से लाईन डालकर अपीलांत की जमीन में डाल दिया है। जबकि अपीलांत को जिस समय जमीन दी गई उसी पर काबिज चले आ रहे हैं। इस नई तरमीम की वजह से अपीलांत को भूमि से बेदखल करने की धमकी दी गई। इसके कारण ही अधिनस्थ न्यायालय में वाद पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी विधि विरुद्ध तरीके से स्वीकार किया जाकर वादी/अपीलांत का वाद पत्र खारिज किया है। जो विधि विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार फरमाई जाकर वादी/अपीलांत के पक्ष में पारित डिक्री दिनांक 30.5.2000 के अनुसार ही नक्शे में तरमीम की जावे तथा रेस्पो0 द्वारा लाल स्याही से मनमाने तरीके से नक्शा के अंदर बीच में नये सिरे से की गई तरमीम को दुरुस्त किया जावे तथा रेस्पो0 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे अपीलांत को विवादित आराजीयात से बेदखल नहीं करें।</p> <p>रेस्पो0 के अधिवक्ता ने बहस में तर्क दिया कि वादी/अपीलांत द्वारा जब पूर्व में उसी आराजीयात को लेकर अधिनस्थ न्यायालय में पेश किया जा चुका है तो उसको पुनः उसी आराजीयात के बाबत दावा पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सीपीसी के प्रावधानों के तहत ही प्रतिवादी/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाकर अपीलांत/वादी का वाद पत्र विधि अनुसार खारिज किया जाकर वादिया को तरमीम के संबंध में सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र किया है। जिस पर वादिया/अपीलांत को समक्ष न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए थी परन्तु वादिया/अपीलांत द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना नहीं कर सीधे ही माननीय न्यायालय में अपील पेश की गई है। इस प्रकार अपीलांत/वादिया द्वारा प्रस्तुत अपील श्रवणाधिकार से बाहर होने से खारिज फरमाई जावे।</p> <p>उभयपक्ष अधिवक्तागणों की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि वादिया/अपीलांत द्वारा विवादित आराजीयात के बाबत अधिनस्थ न्यायालय में उप जिला कलेक्टर करौली के वाद पत्र 188 आर टी एक्ट के तहत प्रकरण संख्या 24/95 दायर किया गया था। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादिया के पक्ष में दिनांक 30.5.2000 में डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण/रेस्पो0 को पाबन्द किया गया था। वादिया /अपीलांत द्वारा नक्शे में वन विभाग द्वारा गलत रूप से की गई तरमीम को दुरुस्त कराने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में वाद पत्र पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय ने वादिया/अपीलांत का वाद पत्र सीपीसी के प्रावधान आदेश 7</p>	

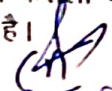
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर



नियम 11 से वाधित होने के कारण खारिज किया जाकर तरमीम को दुरुस्त कराने हेतु समक्ष न्यायालय में चाराजोही करने के लिए निर्देशित किया गया था। अपीलांट/वादिया द्वारा उक्त तरमीम की शुद्धीकरण की कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही नहीं करे सीधे ही इस न्यायालय में अपील पेश की गई है। तरमीम के प्रकरणों की सुनवाई का श्रवणाधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील इस न्यायालय के श्रवणाधिकार में नहीं होने से खारिज योग्य है।

अपीलांट/वादिया तरमीम की शुद्धीकरण हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के लिए स्वतंत्र है।

अपील अपीलांट श्रवणाधिकार के बिन्दु पर खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली के प्रकरण संख्या 3/19 निर्णय दिनांक 9.4.21 की पुष्टि की जाती है।


राजस्व अपील प्राधिकारी
सावाड महाराष्ट्र